गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 136
दि. 15.09.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

'पाकिस्तान का झूठ बनता है कांग्रेस का एजेंडा', प्रधानमंत्री मोदी ने असम से बोला विपक्ष पर हमला

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा बन जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब देश आतंकवादी घटनाओं से लहूलुहान था। ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा बन जाता है। असम में पीएम मोदी ने आज 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने

आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई। उन्होंने कहा कि असम की हेमंता बिस्वा सरमा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने असम के कलाकार भूपेन हजारिका का अपमान किया।

कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा था, 'मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है।' इस दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी खरीदोगे, स्वदेशी खरीदोगे। किसी को गिफ्ट दोगे, तो मेड इन इंडिया होना चाहिए। उसमें भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि अब असम विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालिया पंचायत चुनावों में बीजेपी को जो जीत हुई थी, वह इस बात का सबूत है कि जनता डबल इंजन सरकार के काम से खुश है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और पूर्वोत्तर, खासकर असम, विकास यात्रा में नई पहचान बना रहा है।

सुशासन के 4 वर्ष : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए से अधिक तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना अंतर्गत 161 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता का भुगतान

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 14 सितंबर : 13 सितंबर, 2025 को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुशासन को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू हुई गुजरात की विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य के साथ राज्य के विद्यार्थियों को अमृतकाल में उच्च गुणवत्तायुक्त भविष्योन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मार्च 2024 में दो नई योजनाएँ घोषित की गई थीं : नमो लक्ष्मी योजना तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना।

उल्लेखनीय है कि नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक 10.49 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना अंतर्गत 1.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 161 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता का भुगतान किया गया है।

नमो लक्ष्मी योजना : कक्षा 9 से 12 में अभ्यास के लिए हर छात्रा को चार वर्षों में मिलती है कुल 50 हजार रुपए की सहायता

प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आर्थिक अक्षमता के कारण राज्य की बेटियों को पढ़ाई न छोड़ देनी पड़े और अधिक से अधिक बेटियाँ अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर सकें; इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नमो लक्ष्मी योजना की शुरूआत की थी। इस योजना अंतर्गत राज्य में स्थित गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसएचएसईबी) तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक में अभ्यास कर रही छात्राओं को सहायता देय है। यदि छात्राओं को सरकार की अन्य किसी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा हो, तो भी उन्हें इस योजना का लाभ अतिरिक्त लाभ के रूप में देय है।

नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत कक्षा 9 से 12 में पढ़ाई के लिए छात्राओं को प्रति छात्रा चार वर्ष के दौरान कुल 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

नमो लक्ष्मी योजना शुरू होने से लेकर अब तक राज्य की 10.49 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है।

असम के दरांग में लगभग 6,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के दरांग में लगभग 6,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम की विकास यात्रा के इस ऐतिहासिक दिन पर दरांग के लोगों और असम के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, उन्होंने कल पहली बार असम का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन की शानदार सफलता का श्रेय मां कामाख्या के आशीर्वाद को दिया और उनकी पावन भूमि पर कदम रखते ही आध्यात्मिक संतुष्टि की गहन अनुभूति व्यक्त की। उन्होंने असम में मनाई जा रही जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। लाल किले की प्राचीर से अपने शब्दों को दोहराते हुए, श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति में 'सुदर्शन-चक्र' का विचार प्रस्तुत किया था। श्री मोदी ने मंगलदोई को एक ऐसा स्थान बताया जहां संस्कृति, ऐतिहासिक गौरव और भविष्य की आशा का संगम होता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र असम की पहचान का एक केंद्रीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेरणा और वीरता से भरी इस धरती पर उन्हें लोगों से मिलने और बातचीत करने का अवसर पाकर सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है।

श्री मोदी ने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले ही राष्ट्र ने भारत रत्न और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका की जयंती मनाई थी।

प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी, सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र को हार्दिक शुभकामनाएं दी और हिंदी को भारत की पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर बताते हुए हिंदी के

सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उन्हें गर्व के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: 'आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।'

मणिपुर में भारी बारिश से हजारों घर डूबे, अगले 48 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, रखी जा रही लगातार निगाह

(जीएनएस)।

मणिपुर में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इम्फाल ईस्ट जिले के याइंगांगपोकपी क्षेत्र में बीते 24 घंटों में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ ने करीब एक हजार घरों को प्रभावित कर दिया। कई नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे खतरा और भी बढ़ सकता है।

भारी बारिश के कारण इम्फाल-उखरूल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। सुबह से ही इस मार्ग पर सामान्य यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाढ़ का पानी लेइंगखोंग नाले से उफान मारते हुए आसपास के गांवों और खेतों में घुस गया।

सांती खोंगबल, सेजियांग, सबुंखोक खुन्नौ, नोंगाडा और लामलाई थाने के आसपास की बस्तियां और दुकानें पूरी तरह पानी में डूब गईं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, कई खेत और घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं जिससे भारी नुकसान हुआ है।

इम्फाल के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। इम्फाल वेस्ट जिले के सिंगजामेई ओक्रम से काकवा और सगोलबंद क्षेत्र के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए। इसी तरह, थौबल जिले के वांगजिंग इलाके में कई घर और स्कूल बारिश व बाढ़ से जलमग्न हो गए।

भूस्खलन और मिट्टी खिसकने की घटनाएं

लगातार बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें भी आई हैं। टीएम कासोम में भूस्खलन हुआ है जबकि नोनई जिले के अवांगखुल क्षेत्र और सेनापति जिले के यांगखुल्लेन में भी भूस्खलन दर्ज किया गया है। राज्य की प्रमुख नदियां - इम्फाल, नाम्बुल और नाम्बोल - का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।

वहीं, इरिल और थौबल नदियों का जलस्तर भी चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कांगपोकपी जिले के कांगपोकपी में 44 मिमी और सैकुल में 27 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं, चुराचांदपुर में 45.8 मिमी, चांदेल में 45.2 मिमी, सेनापति में 44.6 मिमी, उखरूल में 42 मिमी और इम्फाल ईस्ट में 41 मिमी बारिश हुई।

आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उखरूल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, जिरीबाम, नोनई, चुराचांदपुर, फेर्जावल और तमेंगलोंग को छोड़कर बाकी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

बता दें कि इसी साल जून में मणिपुर में नदियों के तटबंध टूटने से आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान 1.65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, 35,000 से ज्यादा घर और 76 से अधिक ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस बाढ़ में चार लोगों की मौत भी हुई थी।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में,14 सितंबर 2025 को, महात्मा मंदिर

कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर गांधीनगर, गुजरात में, आयोजित, हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान, गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के कर कमलों से, सचिव,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, श्री वी. श्रीनिवास को, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) प्रदान किया गया।

नई उद्योग नीति में बस्तर संभाग पर विशेष तौर पर फोकस : सीएम

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री साय ने ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में आदिवासी समाज के ईष्ट आराध्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई उद्योग नीति में आदिवासी विकास को प्राथमिकता देते हुए बस्तर सहित सरगुजा को विशेष तौर पर फोकस किया गया है, ताकि यहां के निवासियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ दिलाया जा सके। ब्लॉक मुख्यालय नरहरपुर के उन्मुक्त खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी समाज के ईष्ट देवी-देवताओं का जयघोष करते हुए उपस्थित लोगों को ठाकुर जोहारनी और नवाखाई की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की यह अनूठी परंपरा आगे भी जीवित रहनी चाहिए और समाज की एकजुटता हमेशा बनी रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा आगे बढ़ें, सुशिक्षित बनें, इसके लिए पूरे प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उन्होंने बताया कि आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाएं प्रदेश में संचालित हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसी तरह प्रयास और एकलव्य जैसे श्रेष्ठ संस्थानों के माध्यम से भी लगातार सुधार के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल संचालित है और प्रदेशभर में नालंदा परिसर स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों को माओवाद के विरुद्ध अभियान में लगातार बड़ी सफलताएँ मिल रही हैं। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

मंशानुरूप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से पशुपालन, मुर्गीपालन जैसी रोजगारमूलक गतिविधियों से लोगों को जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका वितरण, रामलला दर्शन योजना सहित ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

मैदान पर भारत ने लिया असली बदला! पहले हराया फिर पाकिस्तानियों को बिना हाथ मिलाए ही लौटाया ड्रेसिंग रूम

(जीएनएस)।

एशिया कप 2025 के महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 127 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने यह लक्ष्य बेहद आसानी से हासिल कर लिया और 25 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की।

भारत की जीत के हीरो बने कप्तान सूर्यकुमार यादव। उन्होंने नाबाद 47 रनों की दमदार पारी खेली और आखिर में छक्के के साथ मैच खत्म किया। सूर्यकुमार ने लेफ्ट-आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर शानदार छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। उनके साथ शिवम दुबे भी नाबाद लौटे। भारत ने यह मैच तीन विकेट खोकर आसानी से अपने नाम किया।

खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ

लेकिन इस मुकाबले के बाद जो दृश्य देखने को मिले, उन्होंने सबको चौंका दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ मिलाने से परहेज किया। मैच खत्म होते ही सूर्यकुमार और दुबे तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए और अपने साथियों के साथ हाई-फाइव कर जश्न मनाया। वहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही हाथ मिलाते दिखे। मैच के दौरान भी जब टॉस हुआ था, तब सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा अली से हाथ नहीं मिलाया था।

ग्रुप स्टेज में भारत ने जीते दो मैच

यह साफ दिखा कि मैदान के बाहर भी दोनों टीमों के रिश्तों में तल्खी मौजूद है। हालांकि दर्शकों के लिए यह मैच रोमांच से भरा रहा, लेकिन खेल भावना के लिहाज से हाथ न मिलाने की यह घटना सुर्खियां बन गई।

आईएनएस त्रिकंड पोत ग्रीस की सलामिस खाड़ी में

भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस जहाज त्रिकंड भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के हिस्से के तौर पर 13 सितंबर, 2025 को ग्रीस की सलामिस खाड़ी में पहुंचा। इस यात्रा के दौरान, आईएनएस त्रिकंड भारत और ग्रीस के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। इस पहल का उद्देश्य आपसी सहभागिता के साथ युद्धक क्षमताओं को बढ़ाना, सामरिक कौशल को परिष्कृत करना और परिचालन तालमेल को विस्तार प्रदान करना है। आईएनएस त्रिकंड सलामीस खाड़ी में बंदरगाह प्रवास के दौरान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग तथा आपसी सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक गतिविधियों में भाग लेगा।

सम्पादकीय

नेपाल को सुशीला कार्की से बड़ी उम्मीदें

नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश से पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करने वाली सुशीला काका ने ऐसे उथल-पुथल के वक्त देश की बागडोर संभाली है जब देश में चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं। एक चुनी हुई गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जेन जेड के युवा आंदोलनकारियों के भरोसे पर खरा उतरना सुशीला के लिए जो चुनौती है उसी में सारी चुनौतियां समाहित हैं। किन्तु पूर्व न्यायधीश के कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी एवं साहसी गुणों के जानकार मानते हैं कि उनका देश के राजनेताओं से तो संबंध अच्छा रहा है किन्तु उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य परायणता से समझौता नहीं किया। जो लोग सुशीला काका को जानते हैं, वह यह भी जानते हैं बाबूराम भट्टराई की सरकार में रहे संचार मंत्री जेपी गुप्ता को दंडित करने में उन्होंने किसी के प्रभाव की परवाह नहीं किया। इसी तरह राजनीति में अत्यन्त प्रभावशाली लोकमान सिंह प्राधिकरण की जांच से हटाना और एक मंत्री को कोर्ट से हथकड़ी लगवा कर जेल भेजने का जो साहसी निर्णय सुशीला ने दिया उससे नैतिकता के उच्च मानदंडों के प्रति उनके सम्मान एवं निष्ठा का प्रमाण मिलता है। राजनेताओं के प्रति उनके संबंध अच्छे रहे किन्तु उनके दुष्कर्मों, भ्रष्टाचार और अपराधों के प्रति वह सदैव असहिष्णु रहीं। जिस मंत्री को सुशीला ने हथकड़ी लगवा कर जेल भेजा था, वह कोई सामान्य राजनेता नहीं था, उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई से लेकर पुष्पदहल 'कमल' प्रचण्ड तक ने उनसे सिफारिश की थी किन्तु जब उन्हें अपने कर्तव्यों और संबंधों में से एक को चुनना पड़ा तो उन्होंने कर्तव्य एवं संवैधानिक उत्तरदायित्व को चुना। इसीलिए तो नेपाल की सेना को भी एहसास हुआ कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला काका से अच्छा शायद ही कोई और मिले। सुशीला काका को रात्रि 9 बजे शपथ दिलाई गई किन्तु उसके पहले लगभग 7 घंटे तक उनके नाम पर मुहर लगने से पहले उनके चरित्र पर विचार-विमर्श हुआ। यह सच है कि देश के तमाम राजनेता आज भी सेना की निगरानी में जान बचाकर दुबके हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी जानकारी देश की जनता को हो चुकी है। इसलिए ये राजनेता जनता के सामने जाने से न सिर्फ शर्मिन्दगी महसूस कर रहे हैं बल्कि उन्हें यह भी पता है कि अब नेपाल की जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, विरासत में मिली संपत्ति और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर गुस्से से प्रेरित जेन जेड के नेतृत्व वालों ने यदि सुशीला काका पर भरोसा किया है तो अब उनका भी दायित्व राष्ट्र के प्रति बढ़ जाता है। अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर सुशीला काका के 6 महीने ही रहना है और इस बीच न्यायिक आयोग से अब उन्हें देश की उन समस्याओं का समाधान तो करना ही होगा, जिसकी वजह से सत्ता और विपक्ष के सभी राजनेता जनाक्रोश के शिकार बने, बल्कि उन युवाओं के इस आंदोलन में घुसे उन स्वार्थ और शरारती तत्वों की जांच कराकर उनको दंडित करने की जरूरत है जिन्होंने सशस्त्र सुरक्षा बल के अत्याधुनिक हथियार लूटकर देश के राजनेताओं एवं उनके परिजनों की हत्याएं कर दी हैं। ऐसे खुराफातियों को स्टेट अथारिटी का एहसास कराएं जिन्होंने कई अरब की राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई और पर्यटकों का मारपीट कर उनका सामान लूट लिया। सुशीला काका को उन कारकों पर भी जांच करा कर नेपाल के राजनेताओं को बताना चाहिए कि जनता का गुस्सा उनके खिलाफ क्यों फूटा और क्यों उन्हें सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। बहरहाल सुशीला काका से उम्मीद है कि वह नेपाल की धरती का दुरुपयोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले शरारती एवं विघटनकारी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और यह साबित करेंगी कि जन्म उनका भले ही पर्वतीय देश नेपाल में हुआ किन्तु उनका उच्च शिक्षा शिवजी की नगरी वाराणसी में हुई। मतलब वह भारत से भी अपने देश के संबंधों को सामान्य एवं सुदृढ़ रखने का प्रयास करेंगी। अन्त में सुशीला काका को देश का वातावरण सामान्य होते ही 6 महीने में चुनाव कराने की व्यवस्था करनी होगी ताकि नेपाल को एक लोकप्रिय सरकार मिल सके।

इसी के साथ नेपाल के मौजूदा सक्रिय राजनेताओं के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है, ताकि वे पाताप करके अपने देश की जनता से माफी मांग सकें। इन राजनेताओं को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने चीन के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की निजी स्वार्थ के लिए सौदेबाजी की है।

पीएम ने गोलाघाट में बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, रखी पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला

(जीएनएस)।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों और असम के लोगों को शारदीय दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने महान आध्यात्मिक विभूति श्रीमंत शंकरदेव की जयंती के महत्व को स्वीकार किया और पूज्य गुरुजनों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पिछले दो दिनों से पूर्वोत्तर में हैं और हर बार जब भी वह इस क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें असाधारण स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने असम के इस हिस्से में अनुभूत विशिष्ट गर्मजोशी और अपनेपन की भावना को रेखांकित किया और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन विकसित असम और विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने घोषणा की कि असम को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ आवंटित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आज दिन में, वह दरांग में थे, जहाँ उन्होंने कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थान पर उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जो असम के विकास पथ को और मजबूती प्रदान करेंगी।

इस बात को रेखांकित करते हुए कि असम, भारत की ऊर्जा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने वाली भूमि है, प्रधानमंत्री ने कहा कि असम से निकलने वाले पेट्रोलियम उत्पाद राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस क्षमता को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने बताया कि वर्तमान स्थल पर पहुँचने से पहले, उन्होंने पास में ही एक अन्य कार्यक्रम में भाग लिया, जहाँ उन्होंने बाँस से बायो-एथेनॉल बनाने वाले एक आधुनिक संयंत्र का उद्घाटन किया और इसे असम के लिए गर्व की बात बताया। एथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही, उन्होंने एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजनाएँ असम में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी, राज्य के विकास में तेजी लाएंगी तथा किसानों व युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन करेंगी। उन्होंने इन पहलों के लिए सभी को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, बिजली, गैस और ईंधन की माँग भी बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहा है और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस का आयात करता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, देश को दूसरे देशों को सालाना लाखों करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जिससे विदेशों में रोजगार और आय में वृद्धि होती है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि भारत अपनी हरित ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ देश में कच्चे तेल और गैस के नए भंडारों की खोज पर भी काम कर रहा है, श्री मोदी ने 'समुद्र मंथन' पहल के बारे में लाल किले से की गई अपनी घोषणा को याद किया। उन्होंने विशेषज्ञों के आकलन को रेखांकित किया कि भारत के समुद्रों में तेल और गैस के प्रचुर भंडार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास के लिए इन संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 'नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन' के शुभारंभ का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत काफी पिछड़ा हुआ था। हालाँकि, आज सौर ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, 'बदलते समय में, तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को वैकल्पिक ईंधन की आवश्यकता है। उन्होंने एथेनॉल को एक व्यवहार्य विकल्प बताया। उन्होंने बताया कि बांस से एथेनॉल बनाने वाले एक नए संयंत्र का आज उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल से असम के किसानों और जनजातीय समुदायों को बहुत लाभ होगा।

श्री मोदी ने बताया कि बायो-एथेनॉल संयंत्र के संचालन के लिए बांस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि सरकार स्थानीय किसानों को बांस की खेती में सहयोग देगी और उसकी सीधे खरीद भी करेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बांस की चिपिंग से संबंधित छोटी इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अकेले संयंत्र से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ पहुँचेगा।

भारत द्वारा अब बांस से एथेनॉल बनाए जाने की बात पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने जनता को उस दौर की याद दिलाई, जब विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में बांस काटने पर जेल हो सकती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनजातीय समुदायों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रहे बांस पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार ने बांस काटने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और इस फैसले से अब पूर्वोत्तर के लोगों को काफी लाभ हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से निर्मित बाल्टी, मग, बक्से, कुर्सियाँ, मेज और पैकेजिंग सामग्री जैसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी उत्पादों के लिए पॉलीप्रोपाइलीन की आवश्यकता होती है, जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग कालीन, रस्सियाँ, बैग, रेशे, मास्क, चिकित्सा किट और वस्त्र

वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित

गांधीनगर, 14 सितंबर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के नारणपुरा इलाके में 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ऐसे समय में राष्ट्र को समर्पित किया, जब गुजरात में ओलंपिक 2036 के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चरों का निर्माण हो रहा है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पधाओं के आयोजन के लिए संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया, राज्य के कृषि मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल, खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समर्मित करते हुए कहा कि खेल भारत की आत्मा है। खेल की शुरूआत भारत में हुई थी और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तब खेल क्षेत्र में अव्वल स्थान पर रहना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने, चयन में पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विश्व खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के अवसर, जैसे बड़े बदलाव आए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वीर सावरकर स्पोर्ट्स संकुल आधुनिक, विशाल और संपूर्ण सुसज्जित है। लोकर्पण से पहले ही यहां दो बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। यहां खेलने आए देश-विदेश के खिलाड़ियों और उनके खेल मंडलों के अध्यक्षों ने वीर सावरकर खेल परिसर की सुविधाओं को विश्वस्तरीय और आधुनिक बताया है।

उन्होंने अहमदाबाद के नारणपुरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर करने के संदर्भ में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर एक कुशल तैराक थे। अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए, उन्होंने बेड़ियों के साथ जहाज से छलांग लगाई और समुद्र को पार करके फ्रांस पहुंच गए थे।

अंग्रेजों द्वारा शासित भारत के इतिहास में 120 वर्ष की दोहरी आजीवन कारावास की सजा पाने वाले एकमात्र क्रांतिकारी वीर सावरकर ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया। अंग्रेजों ने 1857 के संग्राम को सैन्य विद्रोह कहा था, लेकिन वीर सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। श्री शाह ने कहा कि यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसे साहसी वीर सावरकर को समर्पित है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए आएगा, वह अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए पदक जीतने की आशा के साथ आएगा। वीर सावरकर स्पोर्ट्स संकुल, ऐसे खिलाड़ियों को यथार्थ प्रेरणा देगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद देश की खेल राजधानी बनेगा। अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे आधुनिक खेल परिसरों से खेलों की पर्याप्त सुविधाओं का विकास हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि 10 वर्ष पहले यूपीए सरकार में खेल विभाग का बजट 1643 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर अब 5300 करोड़ रुपये हो गया है।

खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन, पोषण चिकित्सा और चोटों आदि पर ध्यान दिया जाता है। देश में एक नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। खेलो इंडिया गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने खेल नीति के संदर्भ में आगे कहा कि भारत के खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच प्रदान करने, खेलों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास करने, खेलों को एक जन आंदोलन बनाने तथा शिक्षा और खेल को एकीकृत करने जैसे पांच स्तंभों पर यह नई खेल नीति आधारित है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद देश के खिलाड़ियों का ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और विंटर गेम्स में प्रदर्शन और अधिक उत्कृष्ट हुआ है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से 2012 तक सभी ओलंपिक में भारत को 20 स्वर्ण पदक मिले थे, जबकि पिछले 8 वर्षों में 15 ओलंपिक पदक मिले हैं। पैरा ओलंपिक में 8 पदक मिले थे, मोदी सरकार के आने के बाद 52 पदक मिले हैं। डेफ ओलंपिक में दो पदक मिले थे जबकि अब 22 पदक मिले हैं।

उन्होंने कहा कि 2029 में अहमदाबाद में पुलिस और फायर विभाग के जवानों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पधाएं आयोजित होने जा रही हैं। 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है, और 2036 में ओलंपिक भी अहमदाबाद में आयोजित हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है।

इस अवसर पर श्री अमित शाह ने वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अत्याधुनिक सुविधाओं पर रोशनी डाली। केंद्रीय मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने वार्ड में निवास स्थान के निकट ही अत्याधुनिक खेल परिसर के आकार लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यहां स्थित 21 एकड़ भूमि पर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी देने की विनती की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आग्रह के साथ स्वीकृति प्रदान की थी कि इस क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय खेल परिसर का निर्माण किया जाना चाहिए, जो इस अत्याधुनिक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ पूरी हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण अवसर पर कहा कि अहमदाबाद और गुजरात को आज विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिल रही है। संविधान के अंगीकार के 75वें वर्ष और देश में मनाए जा रहे हिंदी दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में 825 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित यह परिसर गुजरात को खेल क्षेत्र में एक नई दिशा देगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि 'प्रत्येक क्षेत्र में विकास और विकास के लिए खेल का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में भी कौशल विकास का उल्लेख है। खेल की हमारी विरासत अनेक उदाहरणों की साक्षी है। हमारी इस विरासत को प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' के ध्येय के साथ आधुनिक स्वरूप दिया है।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल नीति और उसके चलते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 पारित करके खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। यह बात साबित करती है कि देश में खेलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा और कौशल दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अहमदाबाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भी अहमदाबाद समर्थ बना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज लोकार्पित हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा।

राज्य में उभरती खेल संस्कृति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में खेल संस्कृति लगातार विकसित हो रही है।

राज्य में खेल क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं कई गुना बढ़ गई हैं। दो दशकों में राज्य के खेल बजट में भी कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। आज राज्य का खेल बजट 486 करोड़ रुपए है, जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य के 21 जिलों में 23 खेल परिसर कार्यान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पास 233 एकड़ क्षेत्र में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा एथलीट हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आकार ले रहा है। यह सिद्ध करता है कि खिलाड़ियों को बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत', स्वदेशी को प्रोत्साहन और जीएसटी सुधारों जैसे प्रशंसनीय कदमों की भी मुख्यमंत्री ने सराहना की।

केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण अवसर को गौरवशाली क्षण बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत यानी 'विकसित भारत, समृद्ध भारत' का निर्माण हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में खेल क्षेत्र में अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसके कारण भारत आज खेल क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की 'विकसित भारत' की संकल्पना में खेल क्षेत्र में हुए विकास कार्य महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के माध्यम से एक मजबूत खेल इकोसिस्टम का निर्माण किया गया है, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अहम साबित होगा। श्री मांडविया ने कहा कि वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आगामी दिनों में खिलाड़ियों के सपनों और मैडलों का गवाह बनेगा। गुजरात के खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात और देश को खेल क्षेत्र की एक अनमोल सौगात के रूप में यह भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया है। श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि तीन वर्ष पहले जब इस कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई थी, तब श्री अमित शाह ने वादा किया था कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर तीस महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। उन्होंने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगातार रुचि दिखाई है और इसके कार्यों की निरंतर समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से देश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा।श्री हर्ष संघवी ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आधिकारिक लोकार्पण से पहले ही वहां कोई अंतरराष्ट्रीय टूनामेंट आयोजित किया गया है।

आयुष मंत्रालय महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान" में शामिल हुआ

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान" में भाग ले रहा है । मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों, आयुष अनुसंधान संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और निजी क्षेत्र, संघों, गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगा।

इस 16-दिवसीय अभियान में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), कैंसर, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं; पोषण एवं स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान अभियान शामिल होंगे। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों में एनीमिया, एनसीडी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी) के लिए आयुष उपचार पर ध्यान दिया जाएगा।

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान जीवनशैली संबंधी परामर्श, योग सत्र और "प्रकृति परीक्षण" के लिए समर्पित कियोस्क के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में जागरूकता शिविर, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ेंगे। लोगों को घरेलू उपचार और पोषण किट वितरित किए जाएंगे

जबकि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सामान्य औषधीय पौधों और हर्बल चाय के स्वास्थ्य लाभों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा बताया जाएगा। यह अभियान आयुर्वेद-प्रेरित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योग-आधारित बचाव विधियों के माध्यम से कॉर्पोरेट बर्नआउट का मुकाबला करने पर भी जोर देता है।

स्वयं सहायता समूह पंचायत स्तर पर समुदायों को संगठित करने के लिए जागरूकता रैलियां और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह अभियान गर्भावस्था से लेकर प्रशामक देखभाल तक, महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेगा। इसके तहत, एनीमिया मुक्त महिलाएं, स्वस्थ मां, तनाव मुक्त महिलाएं, हर्बल पोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य जैसे विषयों पर दैनिक आयुष स्वास्थ्य सुझाव सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे ताकि महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद मिल सके।

हार्दिक पंड्या : पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई नहीं कर सका वो कर दिखाया

(जीएनएस)।

एशिया कप 2025 के सबसे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ी। इस हाई-वोल्टेज मैच में भारतीय टीम ने शानदार शुरूआत की और उसके हीरो बने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या। हार्दिक पंड्या ने इतिहास रचते हुए पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज सैम अयूब का विकेट झटका। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

पहली गेंद पर ही झटक लिया विकेट

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरूआत से ही दबदबा बना लिया। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सैम अयूब को पवेलियन भेजकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इससे पहले भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की पहली गेंद पर विकेट लेने का रिकॉर्ड केवल अर्शदीप सिंह के नाम था, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यह कारनामा किया था।

पाकिस्तान के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाने वाले बने पहले भारतीय

हार्दिक के नाम अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया है। वह भारत के पहले गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ पहली ही गेंद पर विकेट लिया। दुनिया के इतिहास में यह कारनामा करने वाले वह तीसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले श्रीलंका के नुवान कुलसेकरा (2009) और दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे (2021) यह कमाल कर चुके हैं।

बल्लेबाजी में भी खास रिकॉर्ड के करीब

गेंदबाजी में अपनी धार दिखाने वाले हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी में भी एक बड़ा मुकाम हासिल करने के करीब हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके अब तक 91 रन हैं और वह पहले से ही सबसे ज्यादा विकेट (13) लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। अगर इस मैच में वह 9 रन और बना लेते हैं, तो पंड्या भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिनके नाम पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में 100 रन और 10 से ज्यादा विकेट होंगे।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004.
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

तभी एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनेगा जब हमारी बेटियाँ शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगीः लोकसभा अध्यक्ष

(जीएनएस)।

'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' और बाल कल्याण, 2047 तक विकसित भारत के विजन की आधारशिला हैं: लोकसभा अध्यक्ष

नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है, बल्कि महिलाओं को लोकतंत्र में उनका उचित स्थान दिलाने की ऐतिहासिक पहल हैः लोकसभा अध्यक्ष

संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान लैंगिक रूप से निष्पक्ष हो और समानता की आधारशिला बनेः लोकसभा अध्यक्ष

भारत में महिला नेतृत्व की गौरवशाली परंपरा रही है — प्राचीन विदुषियों और स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तक विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं ने नेतृत्व प्रदान कियाः लोकसभा अध्यक्ष

महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए नए कानूनों, नीतिगत सुधारों और पंचायत से संसद तक भागीदारी की आवश्यकता हैः लोकसभा अध्यक्ष

महिला सशक्तिकरण पर समितियों का सम्मेलन विचारों के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समावेशी नीतिनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करता हैः लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर समितियों के ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रविष्टि तिथिः 14 एरढ 2025 4:41ढटु८ ढक्ह ऊे

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल कल्याण पर आधारित 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास'ही 2047 तक विकसित भारत के विजन की आधारशिला है। तिरुपति में संसद और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत तभी एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनेगा जब हमारी बेटियाँ शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी। इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 'विकसित भारत हेतु महिलाओं के नेतृत्व में विकासह्व विषय पर किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से 'लैंगिक उत्तरदायी बजटह्व और 'उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का सामना करने हेतु महिलाओं का सशक्तिकरणह्वपर ध्यान केंद्रित किया गया है। विचार-विमर्श का केंद्रबिंदु होगा—महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना, शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना, समावेशी नीतियाँ सुनिश्चित करना और ऐसे भारत की परिकल्पना

को आगे बढ़ाना जहाँ महिलाएँ केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास की मुख्य निमार्ता भी हों।

श्री बिरला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर समितियों का यह प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है। ऐसे सम्मेलन, उन्होंने कहा, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समावेशी नीतिनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसने देशभर से सांसदों, नीति निमार्ताओं और महिला नेताओं को एक साथ लाकर महिला नेतृत्व, समानता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समावेशन के लिए सामूहिक रूप से रणनीतियाँ तय करने का अवसर प्रदान किया है।

श्री बिरला ने कहा कि तिरुपति सम्मेलन यह स्पष्ट और सशक्त संदेश देता है कि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण परिधीय विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला हैं। पंचायत से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व, समावेशी कानूनों और नीतियों तथा प्रत्येक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता पर केंद्रित यह सम्मेलन 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

लोक सभा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण किसी एक सम्मेलन की ही बात नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए जीवन के प्रत्येक चरण में महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली व्यापक नीतियों की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि नीति-निर्माण एवं कानून-निर्माण संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने से उन चुनौतियों और अवरोधों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिनका महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सामना किया है।

श्री बिरला ने कहा कि जैसे-जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, नारी शक्ति एक अजेय शक्ति के रूप में उभर रही है, जो राष्ट्र को शक्ति और समावेशिता की ओर अग्रसर कर रही है।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति, नेतृत्व और भागीदारी केवल समानता का विषय नहीं है, बल्कि समावेशी और सतत विकास की आधारशिला भी है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, विज्ञान, शासन, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्रों में भारत जिस तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं की भूमिका और उनका सुरक्षित भविष्य ही राष्ट्रीय प्रगति की गति और स्वरूप को निर्धारित करेगा।

इस अवसर पर, श्री बिड़ला ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण किया, जिनके त्याग और समर्पण ने एक अधिक समान और समावेशी समाज की नींव रखी। इन साहसी महिलाओं ने बाधाएँ तोड़ीं, रूढ़ियों को चुनौती दी और नेता, रणनीतिकार तथा परिवर्तनकर्ता के रूप में उभरीं। उनकी विरासत ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता का संग्राम केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि न्याय और समानता के लिए भी एक संघर्ष था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और महिला अधिकारों जैसे क्षेत्रों में उनके कार्यों ने सुनिश्चित किया कि समानता और न्याय के सिद्धांत स्वतंत्र भारत में जीवित बने रहें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान सभा में भी 15 महिला सदस्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा थीं और उनके दृष्टिकोण एवं विचारों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान लैंगिक रूप से निष्पक्ष हो, जिससे महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की मजबूत नींव पड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में निहित स्वतंत्रता और समानता उन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम हैं।

महिला नेतृत्व को रेखांकित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि प्राचीन विदुषियों गार्गी और अनुसूया से लेकर वीरांगनाओं रानी रुद्रमादेवी और रानी लक्ष्मीबाई तक, महिलाओं ने अपने साहस, ज्ञान और त्याग से भारत के इतिहास को गढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय महिलाएँ अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल से लेकर साहित्य, तथा स्थानीय शासन से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। भारत में महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष और विधायक रही हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय है और यह राष्ट्र की महिला नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस संदर्भ में, श्री बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक संवैधानिक सुधार बताया, जिसने इस परिवर्तन को संस्थागत रूप दिया है। उन्होंने गर्व से स्मरण किया कि यह नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक था, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। यह ऐतिहासिक कानून केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि महिलाओं को शासन में उनका उचित स्थान दिलाता है और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने के लिए महिला नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करता है।

'हिंदी दिवस - 2025' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्क्री अध्यक्षता में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 14 सितंबर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'हिंदी दिवस-2025' के अवसर पर 'पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ।

समारोह के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हिंदी भाषा प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि मित्र है। पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होता था। इसमें कुछ बदलाव किए गए और पिछले पांच वर्षों से यह कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमें राजभाषा और देश की सभी भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात में प्रारंभ से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी और उमाशंकर जोशी सहित अन्य कई विद्वानों ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया और इसका प्रचार भी किया। इन दूरदर्शी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के साथ संवाद करने और प्रत्येक राज्य में हिंदी को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में गुजराती और हिंदी का सह-अस्तित्व रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर गुजराती बच्चों की पहुंच बहुत अधिक बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर यह पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन भाषा प्रेमियों को नई दृष्टि, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आज इस सम्मेलन में कई प्रकाशनों का लोकार्पण हुआ है, जो भाषा के प्रति हमारे प्रेम और शैलियों में भाषा के

उपयोग को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि हिंदी बोलचाल और प्रशासन के साथ-साथ विज्ञान, तकनीक और न्याय की भाषा भी होनी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने 'सारथी' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक अनुवाद प्रणाली है, जिसके माध्यम से हिंदी भाषा से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अनुवाद प्रणाली में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसके माध्यम से देश के किसी भी राज्य से किए गए पत्राचार का प्रत्युत्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनकी स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई के दौरान तीन मुद्दों पर बल दिया था- स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। इन तीनों चीजें न केवल एक-दूसरे से बल्कि देश के स्वाभिमान से भी जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी गुजरात राज्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वे जानते थे कि जब तक भाषा मजबूत नहीं होती, तब तक कोई भी समाज दुनिया के सामने उन्नत मस्तक के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा, उन्होंने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' के बारे में बताते हुए कहा कि इस शब्दकोश में लगभग 7 लाख शब्दों को शामिल किया गया है, जो वर्ष 20229 तक दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे बडा शब्दकोश बन जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके हिस्से के रूप में आज पांच दृष्टिबाधित लोगों को एआई-संचालित चश्मे प्रदान किए गए हैं। इस चश्मे की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि एआई-संचालित चश्मे की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी पढ़ सकेंगे, इससे परिचित चेहरों को पहचानने में मदद मिलेगी और वॉइस असिस्टेंट सिस्टम की मदद से करेंसी मुद्रा की पहचान कर सकेंगे। इस प्रकार, यह चश्मा उनके निजी सहायक के रूप में काम करेगा।

श्री शाह ने देश भर के माता-पिता से अपील की कि बच्चों के साथ मातृभाषा में बातचीत करें और उन्हें मातृभाषा में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाएं। अनेक भाषा विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जब बच्चा अपनी भाषा में पढ़ता, सोचता, बोलता, विश्लेषण करता, तर्क करता और अपनी भाषा में निर्णय लेता है, तो उसकी क्षमता लगभग 30 फीसदी बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को मातृभाषा को महत्व देना चाहिए और राजभाषा का सहयोग करना चाहिए। संस्कृति भाषा ने हमें ज्ञान की गंगा दी है, तो हिंदी भाषा ने उस ज्ञान को घर-घर तक पहुंचाया है। जबकि हमारी स्थानीय भाषाओं ने उस ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न तकनीकों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाने का सुंदर काम किया है, जिसके हिस्से के रूप में गृह मंत्रालय में भारतीय भाषा अनुभाग का गठन किया गया है, जो केवल आधिकारिक भाषाओं ही नहीं, बल्कि देश की सभी भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने का काम करता है। देश के लगभग 539 शहरों तथा लंदन, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी आधिकारिक भाषा समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरदार साहब ने स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया है। अब, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाषा और संस्कृति की कड़ी बनाकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' बनाया है।

उन्होंने कहा कि भाषा कोई भी हो,

रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में राजस्व खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और युक्तिसंगत बनाने तथा आधुनिक युग में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नए नियमावली का उद्देश्य राजस्व मद (संचालन और भरण-पोषण खंड) के अंतर्गत सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा और त्वरित निर्णय लेने के माध्यम से सैन्य तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। यह सशस्त्र बलों को आवश्यक संसाधनों की समय पर और उचित लागत पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

इस दस्तावेज में व्यापार में सुगमता को और मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप आदि के साथ-साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता, विशेषज्ञता और योग्यता का उपयोग करना है।

रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद डीपीएम द्वारा विनियमित की जाती है। इसे 2009 में आखिरी बार लागू किया गया था। यह नियमावली सशस्त्र बलों और अन्य हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय में संशोधन के अधीन थी।

डीपीएम चालू वित्त वर्ष के लिए मंत्रालय में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सभी राजस्व खरीद के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रावधान निर्धारित करता है। इस नियमावली को सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ संरेखित करने की अत्यधिक आवश्यकता रही है ताकि खरीद में प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित हो सके।

संशोधित दस्तावेज को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वस्तुओं की खरीद नियमावली के अद्यतन प्रावधानों के साथ संरेखित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख प्रयास के रूप में नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के किये एक नया अध्याय शामिल किया गया है। इससे युवा प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का उपयोग कर सार्वजनिक/निजी उद्योगों, शिक्षाविदों, आईआईटी, आईआईएससी और अन्य प्रतिष्ठित निजी संस्थानों के सहयोग से आंतरिक डिजाइनिंग और विकास के माध्यम से रक्षा वस्तुओं/पुर्जों के स्वदेशीकरण में मदद मिलेगी।

इस क्षेत्र में उद्यम करने के इच्छुक व्यक्तियों/उद्योग की चिंताओं का समाधान विकास अनुबंधों के कई प्रावधानों में ढील देकर किया गया है। विकास चरण के दौरान तरलता क्षति (एलडी) न लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रोटोटाइप के विकास के बाद न्यूनतम एलडी @ 0.1% से लगाया जाएगा। अधिकतम एलडी शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है और केवल अत्यधिक देरी की स्थिति में अधिकतम एलडी शुल्क 10% होगा। इससे उन आपूर्तिकताओं को प्रोत्साहन मिलेगा जो वास्तव में समय सीमा को पूरा करने का प्रयास करते हैं लेकिन थोड़ी देरी से आपूर्ति करते हैं।

इसके अतिरिक्त मात्रा के संदर्भ में पाँच वर्षों तक और विशेष परिस्थितियों में उससे अधिक पाँच वर्षों तक के लिए ऑर्डर की सुनिश्चित गारंटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सफल विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी जानकारी, मौजूदा उपकरण आदि साझा करने के संदर्भ में सेवाओं द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक और प्रावधान पेश किया गया है।

संशोधित दस्तावेज क्षेत्र स्तर/निचले स्तर पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को सशक्त बनाएगा, निर्णय लेने में तेजी लाएगा, निचले-उच्च स्तर के बीच फाइलों की गतिविधि को रोकेगा और आपूर्तिकताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों (सीएफए) को उच्च प्राधिकारियों से संपर्क किए बिना, विलंब की मात्रा की परवाह किए बिना, वितरण अवधि में विस्तार देने के संबंध में अपने वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में अपनाई जा रही वर्त्तमान प्रथा के अनुरूप, कॉलेजिएट निर्णय लेने की अवधारणा को और मजबूत किया गया है। अब सीएफए को यह अधिकार दिया गया है कि वे भागीदारी की कमी की स्थिति में और भागीदारी बढ़ाने के लिए, मामले को अपने वित्तीय सलाहकारों के पास भेजे बिना, बोली खोलने की तिथि को एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं।

विभिन्न हवाई और नौसैनिक प्लेटफार्मों की मरम्मत/रीफिटिंग/रखरखाव की जटिलता को देखते हुए, उपकरणों के डाउनटाइम को कम करने और न्यूनतम विलंब के साथ संचालन के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, ऐसी सभी गतिविधियों के लिए कार्य की वृद्धि में 15% की अग्रिम राशि का प्रावधान किया गया है।

तमिलनाडु में 'वोट चोरी' के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, चेन्नई की सड़कों पर निकाला मार्च

(जीएनएस)।

तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने शनिवार को 'वोट चोरी' (श्ङ्गी उँङ्ग१) के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकताओं ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और चुनावी धांधली के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उनका आरोप है कि हाल के चुनावों में मतदाताओं की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हुई है।

यूथ कांग्रेस का आरोप – लोकतंत्र पर हमला

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वोट की चोरी लोकतंत्र के साथ सीधी धोखाधड़ी है। उनका दावा है कि आम जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर से उठता जा रहा है। चेन्नई में हुए इस मार्च के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली।

चेन्नई में हुए इस मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकताओं का गुस्सा साफ

नजर आया। जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया था।

विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता के वोटों की हेराफेरी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा।

केरल में भी उठा 'वोट चोरी का मुद्दा'

यह विवाद केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। केरल में भी यूथ कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की है। विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमसीर ने कहा कि पुलिस अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अगर कहीं चूक होती है, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

चेन्नई से लेकर केरल तक उठे इन प्रदर्शनों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के हमले और जनाक्रोश के बीच सरकार और चुनाव आयोग इस संवेदनशील मामले पर क्या रुख अपनाते हैं।

चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर लाइन व पावर ब्लॉक के कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी

दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के दूसरे चरण के संबंध में लाइन ब्लॉक व पावर ब्लॉक के कारण प्लेटफार्म संख्या 7, 8 और 9 प्रभावित होंगे। जिसके कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

1. 18,25 सितंबर व 2,9,16,23,30 अक्टूबर और 6 नवंबर 2025 को अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद झ तिरुच्चिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया रेनीगुंटा, तिरुत्तानी, मेलपक्कम, काटपाड़ी एवं वेल्लोर कैंट के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तानी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरंबूर, चेन्नई एग्मोर, तांबरम एवं चेंगलपट्ट स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

2. 14,21,28 सितंबर व 5,12,19,26 अक्टूबर और 2,9 नवंबर 2025 को तिरुच्चिरापल्ली से चलने वाली ट्रेन संख्या 09420 तिरुच्चिरापल्ली झ अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया वेल्लोर कैंट, काटपाड़ी, मेलपक्कम, तिरुत्तानी एवं रेनीगुंटा के रास्ते चलेगी। इस दौरान तिरुत्तानी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

यह ट्रेन चेंगलपट्ट, तांबरम, चेन्नई सेंट्रल, पेरंबूर एवं अरक्कोणम स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा प्रारम्भ करे। ट्रेनों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in ार अवलोकन करे।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करने जा रहा यह खास पहल, युवाओं को होंगे ये फायदे

"समस्या एवं परियोजना-आधारित शिक्षण को डिजाइन थिंकिंग के साथ समन्वयित कर रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशील तकनीकों को पोषित करना" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का आयोजन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT), गोरखपुर के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 19 सितम्बर 2025 तक किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को नवीन शैक्षणिक रणनीतियों से सुसज्जित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें समस्या-आधारित एवं

परियोजना-आधारित शिक्षण को डिजाइन थिंकिंग के साथ एकीकृत कर छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशील सोच को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में कुलपति प्रो. जे. पी. सैनी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

प्रो. सरोज वाईकार गेस्ट ऑफ ऑनर तथा प्रो. दीपक एल. वाईकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम प्रो. एस. के. सोनी, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग, एवं प्रो. प्रभाकर तिवारी, विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. सिखा सिंह एवं डॉ. शेखर यादव (विद्युत अभियांत्रिकी विभाग), डॉ. विजय कुमार वर्मा एवं डॉ. मीनाक्षी चौधरी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग) हैं। साथ ही सह-समन्वयक के रूप में डॉ. निखिल कुमार एवं डॉ. रोहित बाबू (विद्युत अभियांत्रिकी विभाग), तथा डॉ. नेहा मिश्रा एवं डॉ. प्रिंस कुमार सिंह (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग) सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

श्री अमित शाह ने सरदार धाम में फेज-2 कन्या छात्रालय तथा 100 करोड़ रुपए की 'दीकरी दत्तक' योजना का लोकार्पण किया

गांधीनगर, 14 सितंबर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद स्थित सरदार धाम में फेज-2 कन्या छात्रालय और 100 करोड़ रुपए की 'दीकरी दत्तक योजना' (बेटी दत्तक योजना) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरदार धाम स्थित सरदार साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदन किया। उन्होंने सरदार धाम के ट्रस्टियों के साथ संवाद कर राष्ट्र निर्माण में सरदार धाम की भूमिका को लेकर विशेष चर्चा भी की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हर समाज इस तरह से जागरूक बन जाए, तो सरकार का काम आसान और सहज हो जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि पटेल समाज एक ऐसा समाज है, जो अध्ययनकताओं के लिए अध्ययन का एक विषय है। इस समाज द्वारा स्थापित व्यवसाय, रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन सहित सारे विषय अध्ययन के विषय हैं, कि कैसे इन सबमें वर्षों तक वर्चस्व बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पटेल समाज का पूरे गुजरात के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कन्या छात्रालय की शुरूआत को बहुत ही उम्दा कार्य बताते हुए कहा कि मां-बाप बेटियों को हॉस्टल भेजने से घबराते हैं, तब यदि अपने ही समाज द्वारा ऐसी सुरक्षित व्यवस्था विकसित की जाए, तो दूरदराज के गांवों से भी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर आकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक समाज सरदार धाम के सूत्र 'समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण' को स्वीकार कर ले, तो वास्तव में राष्ट्र का श्रेष्ठ निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सरदार धाम की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इस अद्भुत संगठन के माध्यम से 3 हजार बेटियां और 2 हजार बेटे पढ़कर समाज, राज्य और देश का नाम रोशन करें, इस उद्देश्य से समाज के अग्रणियों द्वारा की गई कल्पना धरातल पर हूबहू साकार हुई है, जो प्रसन्नता की बात है।

अपने जीवन के विकास के लिए बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर मजबूत बन सकती हैं, इसके लिए समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने 40 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों और छात्रावासों का दौरा किया है, जिनमें से सरदार धाम में सरदार धाम में विकसित की गई छात्रालय की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए काफी सुंदर और सुविधायुक्त है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने उपस्थित ट्रस्टियों को सुझाव देते हुए कहा कि इस संस्था द्वारा छात्रालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए गुजराती और हिंदी भाषा सीखने की क्लास शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह युवा पीढ़ी मातृभाषा सीखकर समाज की मूल ग्रामीण भाषा को समझ सके और भविष्य में आसानी से समाज की सेवा कर सके। इसके अलावा, उन्होंने संस्था की ई-लाइब्रेरी को और भी समृद्ध बनाने के लिए अन्य लाइब्रेरियों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट होकर, अधिक से अधिक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। इससे यूपीएससी और जीपीएससी के प्रशिक्षण के लिए आने वाले विद्यार्थियों को और अधिक सरलता होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने उद्बोधन में स्वयं को गर्व के साथ लौह पुरुष और अखंड भारत के निमार्ता सरदार वल्लभभाई पटेल का उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का उत्सव देशभर में मनाया जाएगा। उनहोंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति नारी सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए सरदार धाम ने 3 हजार बेटियों के पढ़ने, रहने और भोजन की सुविधा के साथ छात्रावास शुरू कर कन्या शिक्षा की मजबूत नींव रखी है। इसके अलावा, बेटियों के लिए 100 करोड़ रुपए की 'दीकरी दत्तक योजना' का भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि समाज के दानदाताओं के सहयोग से बेटियों का भविष्य उज्ज्वल बन रहा है, इसके लिए दानदाता भी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सफल नेतृत्व में देश की सीमा और सुरक्षा, दोनों मजबूत बनी है। इसके अंतर्गत 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को संपूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2017 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प में सहभागी बनकर, स्वदेशी अपनाने और इस दिवाली स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी करने पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से ऐसे छोटे-छोटे विकास कार्यों के माध्यम से रार्ष्य निर्माण और विकसित भारत में सहयोग देने का अनुरोध किया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरदार धाम के अध्यक्ष श्री रवजीभाई सुतरिया ने महानुभावों का सरदार धाम के 1041 ट्रस्टियों की ओर से स्वागत किया और सरदार धाम के भविष्य के आयोजन पर भी प्रकाश डाला।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा दावा, बोले- कभी हम बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे, बिट्रेन का भी किया जिक्र

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को इंदौर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा आज इंग्लैंड विभाजन की स्थिति में आ रहा है, जबकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद के पतन की भविष्यवाणियों को गलत साबित किया है, एकजुट रहते हुए लगातार प्रगति कर रहा है।

मोहन भागवत ने वैश्विक संघर्षों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों को जिम्मेदार ठहराया और अपनी प्राचीन सभ्यता के चरमोत्कर्ष के दौरान भारत के शांतिपूर्ण नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, "हम कभी बंट गए थे, लेकिन हम उसे भी फिर से मिला लेंगे।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब और नहीं बंटेगा बल्कि एकजुट होकर आगे बढ़ेगा

"भारत ने भविष्यवाणियों को गलत साबित किया"

मोहन भागवत ने याद दिलाया कि कैसे पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल सहित कई वैश्विक नेताओं ने

भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि, भारत ने एकजुट और लचीला रहकर इन सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया।

आज बिट्रेन खुद आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा

भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि जहां चर्चिल ने भारत के विभाजन और अराजकता में गिरने की बात कही थी, वहीं आज बिट्रेन खुद आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि भारत लगातार प्रगति कर रहा है और एकजुट है। उन्होंने कहा कि अतीत में देश का विभाजन हुआ था, लेकिन अब यह एकता और सामूहिक शक्ति को बहाल करने की राह पर है।

भारत ने 3,000 वर्षों तक विश्व का नेतृत्व किया

भारत के प्राचीन इतिहास का जिक्र करते हुए भागवत ने बताया कि जब भारत ने 3,000 वर्षों तक विश्व का नेतृत्व किया, तब कोई वैश्विक संघर्ष नहीं था। उन्होंने आधुनिक वैश्विक कलह का मूल व्यक्तिगत स्वार्थों को बताया, जिन्हें उन्होंने अधिकांश समकालीन समस्याओं की जड़ कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवता की भलाई और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ऐसे स्वार्थों को त्यागना होगा।

"भारतीय परंपरा प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण पर आधारित है"

भारत को आस्था की भूमि बताते हुए, भागवत ने कहा कि जहां दुनिया विश्वास पर चलती है, वहीं भारत इस मायने में अलग है कि यहां आस्था कर्म और तर्क के साथ सामंजस्य बिठाती है। उन्होंने समझाया कि भारतीय परंपरा का विश्वास अंधा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण पर आधारित है।

जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति जीवन के नाटक में अभिनेताओं की तरह हैं, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। उनके अनुसार, किसी का सच्चा स्वरूप नाटक समाप्त होने के बाद ही प्रकट होता है।

वापसी : सौरव गांगुली फिर से बने बंगाल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष

(जीएनएस)।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली एक बार फिर से क्रिकेट प्रशासन की दुनिया में लौट आए हैं। उन्हें रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। सौरव गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। गांगुली के लिए यह जिम्मेदारी बिल्कुल नई नहीं है।

गांगुली पहले भी रह चुके हैं उअइ अध्यक्ष

सौरव गांगुली इससे पहले भी साल 2015 से 2019 तक उअइ अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई का कार्यभार संभाला था और 2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

अब एक बार फिर 'दादा' बंगाल क्रिकेट की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के कुछ ही घंटों बाद गांगुली निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। अब वे 28 सितंबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (AGM) में CAB का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बंगाल क्रिकेट संघ के कामकाज में होंगे बड़े बदलाव

माना जा रहा है कि गांगुली के नेतृत्व में बंगाल क्रिकेट संघ के कामकाज में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उअइ की पूरी कार्यकारिणी में भी बदलाव तय माना जा रहा है। मौजूदा उपाध्यक्ष अमलेन्दु बिस्वास, सचिव नरेश ओझा, कोषाध्यक्ष प्रभीर चक्रवर्ती और संयुक्त सचिव देबब्रत दास का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। खासकर दास को वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

दादा का अनुभव बनेगा ताकत

गांगुली का क्रिकेट और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में लंबा अनुभव रहा है। कप्तान के तौर पर उन्होंने भारतीय टीम को नई पहचान दिलाई। वहीं, बीसीसीआई अध्यक्ष रहते उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिनका असर भारतीय क्रिकेट पर आज भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि उनके उअइ अध्यक्ष बनने से बंगाल क्रिकेट को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

'तुम्हारी बेटी विधवा हुई होती तो क्या खेलते', भारत-पाक मैच पर आगबबूला हुए ओवैसी, इन गुरु पर भी जमकर भड़के

(जीएनएस)।

दुबई में हो रहे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी शिवसेना यूबीटी मैच के विरोध में जहां सड़कों पर प्रदर्शन किया वहीं विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, जिससे यह मामला और भी गरमा गया है।

इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके साथ ही ओवैसी ने भारत के एक प्रसिद्ध गुरु के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

भाजपा शासित राज्यों के सीएम पर निकाला गुस्सा

इससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि, "मेरा सवाल असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत सभी से है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों की पहचान धर्म पूछकर की और फिर उन्हें गोली मार दी, तो क्या आपके पास इतनी ताकत भी नहीं कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर सकें?"

एआईएमआईएम प्रमुख ने भावनात्मक रूप से सवाल उठाया, "अगर तुम्हारी बेटी विधवा हो जाती तो क्या तुम यह मैच खेलते?" उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला, यह कहते हुए कि अगर पीएम ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो फिर वह बीसीसीआई को क्रिकेट मैच के लिए मंजूरी कैसे दे सकते हैं?

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के बयानों को लेकर ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवैसी ने देशवासियों को ऐसी सोच वाले व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ओवैसी ने लिखा, "यह व्यक्ति बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भारत में गृहयुद्ध की धमकी दे रहा था, और अब वह शांतिवादी बन गया है। ट्रंप की बजाय, श्री श्री रविशंकर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भगवान भारत को ऐसे 'राष्ट्रवादियों' से बचाए।"

श्रीश्री रविशंकर ने भारत-पाक मैच पर क्या दिया था बयान?

दूसरी ओर, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "खेलों में राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसा नहीं है। मैं यह फैसला अपने देश के युवाओं पर छोड़ता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे खेलना चाहते हैं तो उन्हें किसी को नहीं रोकना चाहिए। खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करते हैं। खिलाड़ी राजनेता नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं। हमें हर उस रास्ते को तलाशना चाहिए, जिससे हम समाज में और शांति ला सकें।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' और 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे।

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर 2025 को, 8वें पोषण माह के साथ-साथ 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ करेंगे, जो पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (टङ्खलत्रङ्क) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (टङ्खहउऊ) संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है। टङ्खलत्रङ्क देश भर में स्वास्थ्य शिविरों और सुविधाओं के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देगा, जबकि टङ्खहउऊ पोषण माह की गतिविधियों को अभियान के साथ एकीकृत करेगा, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को संगठित करेगा, और बड़े पैमाने पर पोषण परामर्श और नुस्खा प्रदर्शनों का नेतृत्व करेगा। दोनों मंत्रालय मिलकर एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को समग्र और एकीकृत तरीके से पूरा किया जाए।

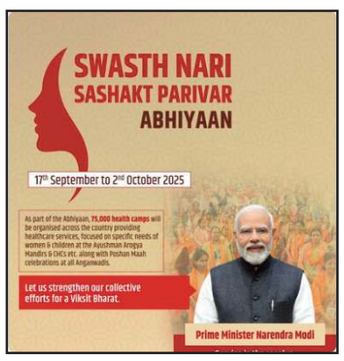

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। यह गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जाँच, शीघ्र पहचान और उपचार संबंधों को मजबूत करेगा, साथ ही प्रसवपूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के

माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह अभियान मोटापे की रोकथाम, बेहतर पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष जोर देते हुए समुदायों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, बेहतर पहुँच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा हितधारकों से आगे आकर इस जनभागीदारी अभियान का अभिन्न अंग बनने की अपील की।

राष्ट्रव्यापी लॉन्च और स्वास्थ्य शिविर

यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर आयोजित किया जाएगा।

एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा।

देश भर में सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

केंद्रीय और राज्य के मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि इस अभियान में शामिल होंगे।

आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थाएँ, शहरी स्थानीय निकाय, माई भारत के स्वयंसेवक और युवा समूह जमीनी स्तर पर सामुदायिक लामबंदी का नेतृत्व करेंगे।

प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ

स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र, ईएनटी, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग और मनोचिकित्सा सहित विशेषज्ञ सेवाएं मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, केंद्र सरकार के संस्थानों और निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

एम्स, रक्षा और रेलवे अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल, सीजीएचएस केंद्र और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) जैसे केंद्र सरकार के संस्थान इन प्रयासों में योगदान देंगे और अंतिम व्यक्ति तक विशेषज्ञ सेवाएँ और निरंतर देखभाल सुनिश्चित करेंगे।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 14 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन

(जीएनएस)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह के आयोजन के साथ ही हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। समारोह में संयुक्त सचिव श्री शेरशा सी. शेख मोहिद्दीन ने हिंदी पखवाड़े का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके उपरांत संयुक्त सचिव श्री राम सिंह ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन का हिंदी संदेश पढ़ा। इस अवसर पर उप महानिदेशक श्री आलोक कुमार वर्मा ने हिंदी दिवस 2025 के उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री जी का संदेश प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर उप महानिदेशक ने कहा कि राजभाषा हिंदी एक भाषा ही नहीं अपितु राष्ट्र के स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का विषय है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वो हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विविध प्रतियोगिताओं में भाग लें। कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 14 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने वाले प्रभागों/अनुभागों के साथ-साथ अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के लिए विगत कई वर्षों से राजभाषा चल शील्ड योजना शुरू की गयी है। इस वर्ष भी यह योजना मंत्रालय के प्रभागों/अनुभागों के साथ-साथ अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के लिए लागू है।

राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने वाले प्रभागों/अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा चल शील्ड से पुरस्कृत किया जाएगा ताकि मंत्रालय के प्रभागों/अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का बढ़ावा मिले, साथ ही राजभाषा हिंदी में कार्य हेतु सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल भी तैयार हो।

सूर्या ने टॉस पर दिखाई पाकिस्तानी कप्तान को तल्खी, क्या हुआ जिसका दर्शकों ने किया फुल सपोर्ट

(जीएनएस)।

एशिया कप में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने अलग तेवर में नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में विरोध के स्वर उठे हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव ने भी तल्खी दिखाई।

टॉस के समय सूर्यकुमार यादव का गुस्सा देखने को मिला। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि सूर्यकुमार यादव कुछ ऐसा करेंगे। सूर्यकुमार यावद और टीम इंडिया को स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से फुल सपोर्ट मिला।

दरअसल जब सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान सिक्का उछाला, टॉस

पाक कप्तान ने जीता लेकिन सूर्या ने कोई हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया। हाथ मिलाना तो दूर की बात है, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान की तरफ देखा तक नहीं। ना ही नजरें मिली और ना हाथ मिले।

टॉस के समय जब सूर्यकुमार यादव बाहर आए, तो दर्शकों से खूब समर्थन प्राप्त हुआ। हूटिंग भी देखने को मिली। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। टॉस हारने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मैं खुद भी पहले फील्डिंग करना चाहता था।

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यूएई के खिलाफ पिछले मैच में खेलने वाले सभी 11 प्लेयर्स को इस बार भी मैदान पर उतारा गया। रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिल पाया। उधर नेशनल एंथम के समय पाक टीम की बेइज्जती हुई। उनके राष्ट्रगान की जगह 'जलेबी बेबी' गाना बज गया।